वित्त विभाग द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

पत्रांक–7/पद सृजन–15–02/2018सा0प्र0 ..../

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

शिवमहादेव प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक........................

विषयः– **बिहार राज्य में जुबेनाईल जस्टिस एक्ट, 2015 के अन्तर्गत जुबेनाईल जस्टिस से जुड़े मामलों के पर्यवेक्षण एवं इसे प्रभावी रूप से लागू करने हेतु अपर निबंधक, जिला न्यायाधीश (प्रवेश बिन्दु) कोटि के 01 (एक) एवं रिसर्च ऑफिसर, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कोटि के 01 (एक) कुल 02 (दो) पद का 30,22,483/– रुपये (तीस लाख बाईस हजार चार सौ तेरासी रुपये) मात्र के कुल अनुमानित वार्षिक व्यय भार पर सृजन की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक–52239 दिनांक 17.07.2018 द्वारा छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय द्वारा अपनाये गये स्टाफिंग पैटर्न को बिहार राज्य में जुबेनाईल जस्टिस एक्ट, 2015 के अन्तर्गत जुबेनाईल जस्टिस से जुड़े मामलों के पर्यवेक्षण एवं इसे प्रभावी रूप में लागू करने हेतु अपर निबंधक, जिला न्यायाधीश (प्रवेश बिन्दु) कोटि के 01 (एक) एवं रिसर्च ऑफिसर, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कोटि के 01 (एक) कुल 02 (दो) पद का 30,22,483/– रुपये (तीस लाख बाईस हजार चार सौ तेरासी रुपये) मात्र के कुल अनुमानित वार्षिक व्यय भार पर सृजन किये जाने की अनुशंसा प्राप्त थी।

2. उक्त अनुशंसा पर सम्यक विचारोपरांत महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के उक्त पत्र के साथ संलग्न संभावित वार्षिक व्यय विवरणी में अंकित पद संवर्ग के सम्मुख अंकित वेतनमान के आधार पर कुल 30,22,483/– रुपये (तीस लाख बाईस हजार चार सौ तेरासी रुपये) मात्र के वार्षिक तथा न्यायिक सेवा सवर्गों में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत भत्तों के अनुमानित व्यय भार पर गैर योजना मद में स्थायी रूप से अपर निबंधक, जिला न्यायाधीश (प्रवेश बिन्दु) कोटि के 01 (एक) एवं रिसर्च ऑफिसर, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कोटि के 01 (एक) कुल 02 (दो) पद के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उपर्युक्त सृजित किये जाने वाले पद का व्यय–बजट शीर्ष "2014 न्याय प्रशासन–लघु शीर्ष–105 सिविल और सेशन्स न्यायालय उप शीर्ष–0001 सिविल और सत्र न्यायालय के अन्तर्गत वेतन एवं भत्ते मद से वहन किया जाएगा, जिसका विपत्र कोड सं0–"N–2014001050001" होगा एवं संबंधित जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

4. इसमें प्रशासी पद वर्ग समिति की स्वीकृति एवं मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नकः–व्यय विवरणी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(शिवमहादेव प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

D /DRIVE /SEC-07/U.S. & D.S.

ज्ञापांक–7/पद सृजन–15–02/2018सा0प्र0 15682 /पटना–15, दिनांक 3.12.18

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक–52239 दिनांक 17.07.2018 के प्रसंग में/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 20.11.2018 के मद संख्या–04 के प्रसंग में/सभी संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3.12.18

सरकार के अवर सचिव।

D /DRIVE /SEC-07/U.S. & D.S.

(

व्यय–विवरणी

संचिका संख्या–7/पद सृजन–15–02/2018

Statement of Anual Estimated Expenditure to be incurred upon the Creation of Posts.

Sl. No.	Name of the Post	Cadre	No. of Post	Pay Scale (P.S.)	Average pay/ Basic pay (Upper Limit of P.S. + Lower Limit of P.S.)/2)	Annual Pay (Average Pay x Number of Post x 12)	Dearness Allowance @ 142% (unrevised)	Total Annual Estimated Expenditures***
1.	Additional Registrar	District Judge (Entry Level)	One (01)	51550-1230-58930-1380-63070	57,310/-	6,87,720/-	9,76,562/-	16,64,282/-
2.	Research Officer	Civil Judge (Sr. Div.)	One (01)	39530-920-40450-1080-49090-1230-54010	46,770/-	5,61,240/-	7,96,961/-	13,58,201/-
							Total	30,22,483/-

{कुल (शब्दों में) –तीस लाख बाईस हजार चार सौ तेरासी रुपये मात्र}

***नोट– उपर्युक्त व्यय के अतिरिक्त समय–समय पर न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को अनुमान्य अन्य भत्ते भुगतेय होगा।

3.12.18

(शिवमहादेव प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

D/DRIVE/SEC-07/VYAY VIVARANI